

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2021—आश्विन 23, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 सितम्बर 2021

क्रमांक एक 6-4/2021/1-7.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8697/2389/21-ब/छ.ग./2021, दिनांक 18-08-2021 द्वारा श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बिलासपुर की सेवाएं, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है.

2. अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बिलासपुर की सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में संयुक्त सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 सितम्बर 2021

क्रमांक 1956/एफ 21/12/2019/13/2/ऊवि.— यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शक्तीकरण हेतु निवेश प्रोत्साहन के लिए जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाये;

2. अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (सन् 10 सन् 1949) की धारा 3-ख सहपठित औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र उद्योगों को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित कालावधि के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है;

सारणी

- (क) विद्युत शुल्क छूट हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-(6.4) में सम्मिलित विवरण के आधार पर सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र नवीन उद्योगों को 01 नवम्बर, 2019 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक तथा विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शक्तीकरण पर 22 अक्टूबर, 2020 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी:-

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा मात्र नवीन उद्योगों के स्थान पर "पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शक्तीकरण" हेतु लागू किया गया)

- (अ) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर को छोड़कर) उद्योग:-

क्षेत्र (1)	सामान्य उद्योग (2)	प्राथमिकता उद्योग (3)	उच्च प्राथमिकता उद्योग (4)
श्रेणी-अ परिशिष्ट-1 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 04 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी-ब परिशिष्ट-1 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी-स परिशिष्ट-1 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(1)	(2)	(3)	(4)
श्रेणी-द परिशिष्ट-1 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.

टीप :- कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी.

(ब) कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योग— इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा कोर सेक्टर के उद्योगों के "अ" एवं "ब" श्रेणी विकासखण्ड के उद्योगों के लिए भी विद्युत शुल्क घोषित करते हुए श्रेणी "स" एवं "द" विकासखण्ड के उद्योगों के लिए छूट की मात्रा एवं अवधि में वृद्धि की गई है।)

1	श्रेणी अ (परिशिष्ट-1 (अ))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट.
2	श्रेणी ब (परिशिष्ट-1 (ब))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक पूर्ण छूट.
3	श्रेणी स (परिशिष्ट-1 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट.
4	श्रेणी द (परिशिष्ट-1 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.

टीप:- कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(ख) औद्योगिक नीति, 2019-24 के परिशिष्ट-6.21 में सम्मिलित विवरण के आधार पर औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत "स्टार्टअप पैकेज" को दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी है:-

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

क्षेत्र की श्रेणी (1)	विवरण (2)
श्रेणी अ (परिशिष्ट-1 (अ))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक पूर्ण छूट.

(1)	(2)
श्रेणी ब (परिशिष्ट-1 (ब))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी स (परिशिष्ट-1 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी द (परिशिष्ट-1 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.

- (ग) औद्योगिक नीति, 2019-24 के परिशिष्ट-6.22 में सम्मिलित विवरण के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित) के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शक्तीकरण प्रकरणों में विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी है:-

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है.)

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
(1)	(2)	(3)	(4)
श्रेणी-अ परिशिष्ट-1 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी-ब परिशिष्ट-1 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी-स परिशिष्ट-1 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी-द परिशिष्ट-1 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट.

टीप :- कैपिटल उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी.

3. उद्योगों की श्रेणियां (Categories of Industries)

3.1 राज्य में "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" की दृष्टि से उद्योगों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम, मध्यम उद्यम, मध्यम सेवा उद्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, की श्रेणी में रखा गया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से इन उद्योगों की परिभाषा वही मान्य ही जायेगी जो कि औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 के अंतर्गत वर्णित है।

3.2 "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" की दृष्टि से उद्योगों को उच्च प्राथमिकता उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, सामान्य उद्योग, कोर सेक्टर उद्योग, संतृप्त उद्योग के वर्गों में वर्गीकृत किया है तथा राज्य के सभी विकासखण्डों को औद्योगिक विकास एवं पिछड़ेपन की दृष्टि से क्रमशः अ, ब, स एवं द श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो कि परिशिष्ट-1 (अ), परिशिष्ट-1 (ब), परिशिष्ट-1 (स) एवं परिशिष्ट-1 (द) अनुसार है।

(औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 अ, ब, स एवं द अनुसार)

3.3 कोर सेक्टर के उद्योग से आशय है कि मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स अंतर्गत स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्युमिनियम संयंत्र।

(औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-5 अनुसार)

3.4 सामान्य श्रेणी के उद्योग से आशय है कि—उच्च प्राथमिकता उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग तथा कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग।

3.5 (अ) औद्योगिक नीति में "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" की दृष्टि से उद्यमी/निवेशकों को निम्नांकित अनुसार वर्गीकृत किया गया है:—

1. सामान्य वर्ग के उद्यमी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी।
3. अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.) निर्यातक निवेशक, विदेशी तकनीक वाले उद्योग।
4. महिला उद्यमी एवं तृतीय लिंग।
5. राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, दिव्यांग (निःशक्त) उद्यमी।
6. राज्य के महिला स्वसहायता समूह को महिला वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होगी।
7. राज्य के एफपीओ (Farmers Producer Organisations) को सामान्य वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होगी।

3.5 (ब) निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:—

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग।
2. मध्यम उद्योग।
3. वृहद उद्योग।
4. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स।

4. उपरोक्त छूट, निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

4.1 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केपिटव पावर प्लांट के मामले में, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के निर्धारण हेतु संस्थान को स्व-घोषित प्रमाण पत्र को ग्रिड कनेक्टिविटी के अनुसार राज्य के भार प्रेषण केन्द्र एवं पीजीसीआईएल के क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

- 4.2 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पावर प्लांट के मामले में छूट की पात्रता, ऑक्जलरी खपत तथा विद्युत नियम, 2005 में परिभाषित केप्टिव यूज में खपत की गई बिजली की यूनितों के आधार पर देय होगी. तदनुसार, संस्थान को केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट हेतु कंपनी को प्रत्येक माह के लिये पृथक-पृथक खपत का विवरण मीटर रीडिंग सहित मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा.
- 4.3 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पावर प्लांट के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिये वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख का निर्धारण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा.
- 4.4 विद्युत शुल्क भुगतान से छूट का आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के अथवा अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है.
- 4.5 औद्योगिक नीति 2019-24 में विनिर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची परिशिष्ट-2 में संलग्न है.
- 4.6 औद्योगिक नीति 2019-24 में विनिर्दिष्ट प्राथमिकता उद्योगों की सूची परिशिष्ट-3 में संलग्न है.
- 4.7 औद्योगिक नीति 2019-24 में विनिर्दिष्ट संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची परिशिष्ट-4 में संलग्न है.
- 4.8 औद्योगिक नीति 2019-24 में विनिर्दिष्ट कोर सेक्टर से संबंधित उद्योगों की सूची परिशिष्ट-5 में संलग्न है.
- 4.9 राज्य में 'स' एवं 'द' श्रेणी के पिछड़े विकासखंडों में राईस मिल/पारबाईलिंग इकाई की स्थापना को सामान्य उद्योग श्रेणी हेतु घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता होगी.
- 4.10 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.) निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को कंडिका-2 में दर्शित अनुसार, दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी.
- 4.11 राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों को कंडिका-2 में दर्शित अनुसार, सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत से अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी.
- राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति, 2019-24 में सम्मिलित परिशिष्ट-6.22 की उपकंडिका 6.22.4 में वर्णित अनुसार छूट दिनांक 22.10.2020 से उपलब्ध होगी.
- 4.12 यदि कोई निवेशक कंडिका 4.10 एवं 4.11 दोनों श्रेणी अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त लाभ हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के अतिरिक्त लाभ की पात्रता होगी.
- 4.13 नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन-भू-आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी.

- 4.14 राज्य में औद्योगिक/वाणिज्यिक भूमि पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना/पूर्व से स्थापित उद्यम में विस्तार करने पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायत की पात्रतानुसार होगी.
- 4.15 राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी.
- 4.16 औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका (21) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित/घोषित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सामान्य उद्योगों (उपरोक्तानुसार पैरा-2 की सारणी में दर्शित अनुसार) की भांति छूट की पात्रता होगी.
- 4.17 रु. 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद् में Bespoke Policy के अंतर्गत विचार कर निर्णय लिया जावेगा.
- 4.18 जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों के द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत उद्योग के स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है उन्हें यह अवसर उपलब्ध होगा कि वे औद्योगिक नीति 2014-19 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प चुन सकेंगे. किंतु इस हेतु उन्हें उद्यम अकांक्षा/आई.ई.एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामले में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा. एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा. विकल्प चयन न किये जाने की स्थिति में इकाई जिस नीति के कार्यकाल में उत्पादन में आएगी, उस स्थिति को लागू औद्योगिक नीति का लाभ लिए जाने की पात्रता होगी. विकल्प परिवर्तन की स्थिति में अथवा कोई विकल्प न लिए जाने की स्थिति में इकाई को पूर्व नीति के अंतर्गत प्राप्त किये गये लाभों को वापस किया जाना अनिवार्य होगा. विकल्प चयन के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस में विकल्प चयन की सूचना संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा.
- 4.19 औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित की गयी कंडिकाओं में वर्णित संस्थाओं को छोड़कर अन्य भारत शासन, राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों (यदि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधानित न हो) को औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होंगे.
- 4.20 औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित किये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने लिए उद्यम में स्थाई नियोजन में अकुशल कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत, तथा प्रशासकीय/प्रबंकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत, रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
- 4.21 यदि किसी निवेशक द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में प्रतिस्थापना हेतु पुर्वानुमति प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण कर उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, तो उसे औद्योगिक नीति 2019-24 की सुविधाएं दिनांक 1 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक उत्पादन में आने पर ही प्राप्त होगी. इसके पश्चात् उत्पादन प्रारंभ होने पर आगामी औद्योगिक नीति के प्रावधान लागू होंगे.

- 4.22 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएँ वही होगी जो औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 में दी गई है.

5. **आवेदनों का निपटारा तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने की प्रक्रिया-**

- 5.1 औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उद्योग में निवेश के आकार, उद्योगों की श्रेणी, निवेशक के वर्गीकरण, उद्योगों के नवीन होने, शक्तीकरण, बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन आदि से संबंधित न होने, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक आदि के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट होंगे.
- 5.2 उद्योग आयुक्त/संचालक अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, अनुशंसित आवेदन, जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, इकाईयों की श्रेणी, उद्योग की स्थिति, निवेश की सीमा, वास्तविक निवेश, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख, विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता अवधि के विवरण अंतर्विष्ट होंगे, मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित किये जायेंगे.
- 5.3 औद्योगिक इकाई, औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य के मूल निवासियों के लिए निर्धारित प्रतिशत तक उन्हें (अकुशल कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत, तथा प्रशासकीय/प्रबंकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत) नियोजित करेगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से निर्धारित अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए रोजगार के संबंध में, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात् आयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग तथा उद्योग केन्द्र अपनी अनुशंसा सहित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिवस के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित करेगा. अपूर्ण अनुशंसित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.
- 5.4 मुख्य विद्युत निरीक्षकालय अनुशंसित आवेदन का परीक्षण करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु ऊपर सारणी में दर्शायी गई कालावधि के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी करेगा.
- 5.5 मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में अनुबद्ध किसी भी शर्त अथवा औद्योगिक नीति 2019-24 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता निरस्त समझी जायेगी.
- 5.6 उपर्युक्त पैरा 5.5 में छूट हेतु पात्रता के रद्द किये जाने की दशा में, उद्योग को ब्याज सहित विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लाभ को राज्य कोषालय में ऐसी तारीख से जमा करना आवश्यक होगा जिससे उद्योग निर्योग्य हो गई हो. यदि उद्योग द्वारा ऐसे बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रभारित एवं वसूल की जायेगी.
- 5.7 विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की सुविधा प्राप्त करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पात्रता प्रमाण जारी करने उपरान्त मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में, ऐसे विषय का निराकरण छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के नियम 13 के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और यह निर्णय, पक्षकारों पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

6 अपील/वाद

- 6.1 कण्डिका 5.1 से 5.3 में वर्णित अनुसार उद्योग विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रक्रिया अर्थात् उद्योग आयुक्त/संचालक अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुशंसित आवेदन जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, इकाई की श्रेणी, उद्योग की स्थिति निवेश की सीमा, वास्तविक निवेश वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख जैसे कार्य हेतु किसी भी विवाद के मामले में उद्योग विभाग द्वारा प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी. इस हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अपील प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा. शुल्क का भुगतान उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ में विहित रीति के अनुसार किया जाना होगा.

निर्धारित समयावधि के पश्चात 90 दिवस की समयावधि के विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के विषय में आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को यह अधिकार होगा कि ऐसे आवेदन पत्रों के विषय में अपरिहार्य परिस्थितियों में हुए विलंब को गुण-दोष के आधार पर शिथिल करने के विषय में निर्णय ले सकेंगे, किन्तु इस हेतु यह आवश्यक होगा कि उपरोक्त निर्णय के विषय में संपूर्ण विवरण लिपिबद्ध किया जाकर कारण दर्शाते हुए निर्णय पारित किया जाए.

निर्धारित समयावधि के पश्चात 91 दिवस से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की समयावधि तक विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के विषय में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे आवेदन पत्रों विषयों में अपरिहार्य परिस्थितियों में हुए विलंब को गुण-दोष के आधार पर, को शिथिल करने के विषय में निर्णय ले सकेंगे, किन्तु इस हेतु यह आवश्यक होगा कि उपरोक्त निर्णय के विषय में संपूर्ण विवरण लिपिबद्ध किया जाकर, कारण दर्शाते हुए निर्णय पारित किया जाए.

एक वर्ष से अधिक विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र इन नियमों के अंतर्गत छूट हेतु पात्र नहीं होंगे.

- 6.2 कण्डिका 5.4 में वर्णित अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा उद्योग संचालनालय/संचालक अथवा आयुक्त द्वारा अनुशंसित आवेदन के निर्णय पर ऊर्जा विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी.
- 6.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अपील प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा. ऊर्जा विभाग के अपील प्रकरणों के संबंध में उपरोक्तानुसार अपील शुल्क ऊर्जा विभाग के संबंधित मद (0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्तियाँ) में देय होगी.
- 6.4 ऊपर पैरा-6.1 एवं 6.2 अनुसार अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित अपीलीय अधिकारी को प्राप्त रहेगी. अपीलीय अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

7. औद्योगिक नीति, 2019-24 के ऐसे कंडिका जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है एवं पात्रताधारित उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने हेतु आवश्यक है वह कंडिकाएं इस अधिसूचना में प्रभावशील समझी जावेगी. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन किये जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इस अधिसूचना में यथास्थिति लागू होंगे.
8. यह अधिसूचना दिनांक 01.11.2019 से प्रभावशील होगी तथा औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 01.11.2019 को/के पश्चात् तथा 31.10.2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले पात्र उद्योगों पर लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

परिशिष्ट-1 (अ)

[औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (अ) अनुसार श्रेणी-अ (विकसित क्षेत्र-15)]

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	बिलासपुर	बिल्हा
2.	कोरबा	कोरबा, पाली
3.	रायगढ़	रायगढ़, खरसिया
4.	दुर्ग	दुर्ग, धमधा
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
6.	रायपुर	धरसीवा, तिल्दा
7.	जांजगीर-चांपा	अकलतरा, बम्हिनीडीह (चांपा)
8.	बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा, सिमगा, बलौदाबाजार

परिशिष्ट-1 (ब)

[औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (ब) अनुसार श्रेणी-अ (विकासशील क्षेत्र-25)]

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	कोरबा	कटघोरा, करतला, पोड़ी-उपरोड़ा
2.	मुंगेली	पथरिया, मुंगेली
3.	रायगढ़	घरघोड़ा, तमनार, पुसौर
4.	दुर्ग	पाटन
5.	कवर्धा	कवर्धा, पण्डरिया
6.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खैरागढ़
7.	बलौदाबाजार	पलारी
8.	धमतरी	धमतरी, कुरुद, मगरलोड़
9.	महासुमंद	महासुमंद, सरायपाली, बागबहरा
10.	रायपुर	अभनपुर, आरंग
11.	बिलासपुर	तखतपुर, मस्तूरी

परिशिष्ट-1 (स)

[औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (स) अनुसार श्रेणी-अ (पिछड़े क्षेत्र-40)]

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	मुंगेली	लोरमी
2.	बालोद	गुंडरदेही, गुरुर, बालोद, डौंडीलोहारा, डौंडी
3.	बेमेतरा	बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़
4.	कवर्धा	बोड़ला, सहसपुर-लोहारा
5.	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़, कसडोल
6.	धमतरी	नगरी
7.	गरियाबंद	छुरा, गरियाबंद, फिंगेश्वर
8.	महासमुंद	बसना, पिथौरा
9.	कांकेर	कांकेर, चारामा
10.	बिलासपुर	कोटा, पेण्ड्रा रोड (गौरेला-1), पेण्ड्रा (गौरेला-2)
11.	जांजगीर-चांपा	बलौदा, नवागढ़, सक्ती, जैजेपुर, मालखरौदा, डभरा, पामगढ़
12.	रायगढ़	धरमजयगढ़, लैलूंगा, सारंगढ़, बरमकेला
13.	राजनांदगांव	छुईखदान
14.	बस्तर	जगदलपुर
15.	सरगुजा	अम्बिकापुर
16.	सूरजपुर	सूरजपुर

परिशिष्ट-1 (द)

[औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (द) अनुसार श्रेणी-अ (अति पिछड़े क्षेत्र-66)]

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	बस्तर	बकावण्ड, बस्तानार, दरभा, लोहण्डीगुडा, बस्तर, तोकापाल
2.	बीजापुर	बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, उसूर
3.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआंकोण्डा
4.	कांकेर	अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोण्डल, नरहरपुर, कोयलीबेड़ा
5.	कोण्डागांव	केशकाल, कोण्डागांव, बड़ेराजपुर, माकड़ी, फरसगांव
6.	गरियाबंद	देवभोग, मैनपुर
7.	नारायणपुर	नारायणपुर, ओरछा (आबुझमाड़)
8.	सुकमा	कौंटा, छिंदगढ़, सुकमा
9.	बिलासपुर	मरवाही
10.	राजनांदगांव	मोहला, छुरिया, अंबागढ़-चौकी, मानपुर
11.	बलरामपुर	बलरामपुर, कुसमी, राजपुर, रामचन्द्रपुर, शंकरगढ़, वाङ्गफनगर
12.	जशपुर	जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला, मनोरा, कांसाबेल, फरसाबहार
13.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, भरतपुर, खड़गवा, सोनहत
14.	सरगुजा	लुण्ड्रा, सीतापुर, बतौली, लखनपुर, मैनपाट, उदयपुर
15.	सूरजपुर	प्रतापपुर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओड़गी, रामानुजनगर

परिशिष्ट-2**औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची-**

(औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-2 के अनुसार)

1. हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग.
2. आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3. फार्मास्यूटिकल उद्योग
4. व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पादन.
5. रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिक के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद.
6. जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद.
7. टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम फेब्रिक्स एवं रेडीमेड गारमेंट्स व अन्य प्रक्रिया) (नॉन ओवन फेब्रिक बैग्स को छोड़कर)
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा टेक्सटाईल उद्योग की प्रविष्टि को उपरोक्तानुसार संशोधित किया गया है.)
8. रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स.
9. निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कंपनी एवं भारतीय कंपनियों के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग.
10. निर्यातक उद्योग.
11. जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाइनरी (मार्कफेड से खरीफ फसल के उपार्जित अतिरिक्त धान क्रय किये जाने की शर्त पर तथा सहकारी शक्कर कारखानों आधारित)
 - 11.1 मार्कफेड से खरीफ फसल के उपार्जित अतिरिक्त धान क्रय किये जाने की शर्त के आधार पर स्थापित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाइनरी,
 - 11.2 राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों के उत्पाद/उपोत्पाद के आधार पर स्थापित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाइनरी,
 - 11.3 राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों के उत्पाद/उपोत्पाद के आधार पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में स्थापित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाइनरी,
 - 11.4 निजी निवेश से स्थापित, समर्थन मूल्य पर खरीद की शर्त पर, गन्ना आधारित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाइनरी,
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 30 जुलाई, 2020 के द्वारा अनुक्रमांक 11.1 से 11.4 तक प्रविष्टियां जोड़ी गई.)
12. इलेक्ट्रिक दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन एवं उनके बैटरी निर्माण.

13. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के उपकरण निर्माण
14. एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ)
15. राज्य में उत्पादित फल, फूल, सब्जी एवं अन्य हार्टीकल्चर उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग
16. भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयां (प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी)
17. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जावें.
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-01/2019/11/6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा अनुक्रमांक 16 पर नई प्रविष्टि को जोड़ा गया एवं अनुक्रमांक 16 की प्रविष्टि को अनुक्रमांक 17 पर प्रतिस्थापित किया गया।)

- टीप :-** 1. उच्च प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा में उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा.
2. यदि किसी उद्योग द्वारा उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी.

परिशिष्ट-3

औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत प्राथमिकता उद्योगों की सूची-

(औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-3 के अनुसार)

(अ) वर्गीकरण के आधार पर-

1. साईकिल एवं साईकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पादन/उपकरण/स्पेयर्स
2. प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
3. नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद.
4. एल्यूमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद.
5. भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी को छोड़कर)
6. ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
7. नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण.
8. विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण.
9. जेम्स एवं ज्वेलरी

10. मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
11. स्पोर्ट्स गुड्स
12. कोयले से द्रव्य ईंधन/गैस/पेट्रोलियम उत्पाद
13. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जावें
14. जैविक खाद, जैविक कीटनाशक एवं बोनमील का निर्माण.

टीप :- 1. प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा.

2. यदि किसी उद्योग द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी.

(ब) उत्पाद आधारित

1. मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी.व्ही.सी. पाईप्स एवं फिटिंग, हाऊस होल्ड प्लास्टिक के आयटम
2. ट्रांसमिशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण
3. स्व-चलित कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स/एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स
4. बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)
5. लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)
6. पलाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
7. रेडीमेट गारमेंट्स (जिनमें यंत्र एवं संयंत्र में न्यूनतम 25 लाख रूपयों का पूंजी निवेश हो)
8. सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाइजर्स
9. वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
10. कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
11. फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाइट, पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पॉलिशिंग तथा टाईल्स निर्माण
12. पोलिस्टर स्टेपल फाईबर
13. ग्रामोद्योग इकाईयां यथा पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबून एवं वाशिंग पावडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सीएफएल बल्ब, स्टील विंडो/डोर/रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश 10 लाख रुपये.
14. सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रुपये 10 लाख)
15. वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश में रुपये 25 लाख हो)

16. हैंड पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण
17. सबमर्सिबल पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण
18. इलेक्ट्रिक मोटर एवं स्पेयर्स का निर्माण
19. ग्रेन साइलो
20. प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री
21. पेन्ट/डिस्टेम्पर
22. पोहा, मुरमुरा
23. नान प्लास्टिक बैग्स
24. ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं

- टीप :-**
1. प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा.
 2. यदि किसी उद्योग द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी.

परिशिष्ट-4

औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची

(औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4 के अनुसार)

(औद्योगिक नीति की कंडिका 16.1 के अंतर्गत वर्णित परिभाषाओं के बिन्दु क्रमांक-15 के संदर्भ में)

1. विलोपित
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 01.06.2020 के द्वारा अनुक्रमांक 1 पर वर्णित एल्कोहल, डिस्टिलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बैवरेजेस को विलोपित किया गया.)
2. आरा मिल (सॉ मिल)
3. सभी प्रकार के पोलिथिन बैग, प्लास्टिक के डिस्पोजल उत्पाद,
4. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
5. स्लाटर हाउस (बूचड खाना)
6. पैकड ड्रिंकिंग वाटर
7. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
8. चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाइट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

9. एस्बेस्टस एवं उस पर आधारित उद्योग
10. लेदर टैनरी
11. स्पंज आयरन (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
12. एकीकृत स्टील प्लांट (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
13. तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
14. स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
15. राईस मिल एवं परबॉईलिंग इकाई (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
16. सभी प्रकार के उत्पादों की रिपैकिंग.
17. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये.

टीप :- संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी.

परिशिष्ट-5

औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत कोर सेक्टर उद्योगों की सूची

(औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-5 के अनुसार)

“औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन” की दृष्टि से निम्नांकित मध्यम, वृहद/मेगा/अल्ट्रा प्रोजेक्ट्स कोर सेक्टर की श्रेणी के उद्योग:-

1. स्टील संयंत्र
2. सीमेंट संयंत्र
3. ताप विद्युत संयंत्र
4. एल्युमिनियम संयंत्र

टीप :- औद्योगिक नीति 2019-24 के अधि में “स” एवं “द” श्रेणी विकासखण्डों में प्रस्तावित एवं स्थापित किये जाने वाले कोर सेक्टर के नवीन उद्योगों को इस नीति में अन्यथा कोई अपात्रता न होने की स्थिति में मात्र स्टाम्प शुल्क से छूट, विद्युत शुल्क से छूट एवं दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान उत्पादन दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए की पात्रता होगी.

संशोधन – दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से जारी स्पष्टीकरण/संशोधन –

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक नीति की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/6 दिनांक 31.10.2019 के परिशिष्ट-5 में वर्णित टीप की अंतिम पंक्ति “स्टाम्प शुल्क से छूट”, विद्युत शुल्क छूट की पात्रता इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित अनुसार तथा दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान के मामले में उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये पात्रता होगी.

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित टीप को समावेशित किया गया है.)

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्रमांक/05/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	ताकम प.ह.नं. 09	0.11	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेरला जिला- बेमेतरा छ.ग.	तकम एनीकट कम काज वें पहुंच मार्ग में प्रभावित ग्राम-ताकम.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोस्कर विलास संदीपान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 07/अ-82/2016-17/4307.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड
(ग) नगर/ग्राम-भस्कुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.333 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
437/1	0.053
437/2	0.072
437/3	0.065

(1)

(2)

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

437/4

0.053

385/4

0.045

385/3

0.045

योग

6

0.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 11/अ-82/2014-15/4299.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

(ख) तहसील-पेण्ड्रा

(ग) नगर/ग्राम-देवरीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

17/2, 18/2

0.210

योग

2

0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

(ख) तहसील-पेण्ड्रा

(ग) नगर/ग्राम-कोड़गार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.799 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

124/3

0.113

280/5

0.057

148/1

0.008

265/7

0.028

124/5

0.065

204/1ख

0.057

264/2

0.040

128/2

0.024

265/3,

0.113

267/1

0.040

266

0.158

117/2

0.085

173/2

0.016

239/3

0.049

128/4

0.121

128/1

0.085

148/2

0.113

212/1

0.138

205/3

0.138

113/1

0.008

264/4

0.032

276/2, 264/6

0.045

238/2

0.113

241/2

0.081

127/5

0.020

(1)	(2)
147	0.016
204/2	0.040
129	0.016
172/2	0.040
172/3	0.045
128/3	0.024
174/6	0.166
212/4	0.008
124/1	0.045
202/1	0.166
280/2	0.045
100/4	0.028
114/2	0.004
115/1	0.012
173/1	0.045
127/1	0.028
116/1	0.113
150/2	0.166
योग	44
	2.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/1	0.025
450/3	0.036
योग	2
	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्ी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरैला-पेण्डा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 21/अ-82/2017-18/4301.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

गौरैला-पेण्डा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 19/अ-82/2017-18/4303.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरैला-पेण्डा-मरवाही
- (ख) तहसील-पेण्डारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मेढुका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरैला-पेण्डा-मरवाही
- (ख) तहसील-पेण्डारोड
- (ग) नगर/ग्राम-खन्ता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.948 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
515	0.235
541/1	0.061
541/2	0.089
551/3, 554/9	0.053
542	0.364
544	0.146
योग	7
	0.948

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मसूरीखार एनीकट योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(1)

(2)

469

0.049

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

168/1

0.097

337/1

0.024

472/3

0.101

465/3

0.134

402/4

0.069

437/5

0.263

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

योग

24

2.129

प्र. क्रमांक 20/अ-82/2017-18/4305.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्जी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही

(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड

(ग) नगर/ग्राम-बरवासन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

401/1

0.036

468/3ख

0.081

342

0.097

437/2

0.210

437/3

0.012

465/1

0.061

402/1

0.065

348/1

0.125

337/2

0.024

338

0.049

467

0.032

402/3ख

0.032

468/3क

0.138

468/1

0.134

341

0.020

471/2

0.190

336/2

0.085

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 30/अ-82/2015-16/4297.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही

(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड

(ग) नगर/ग्राम-भस्कुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.173 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

257/3

0.085

454/6

0.093

718/2

0.093

464/3

0.081

454/2

0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
265/1	0.178	464/1क	0.202
464/2	0.085		
210/1	0.061	योग	18
257/2	0.085		2.173
257/4	0.085	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.	
718/3	0.117		
265/2	0.231		
464/4	0.081	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.	
718/4	0.109		
464/1ख	0.202		
464/5	0.073	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
218/2	0.170	नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

अंतागढ़, दिनांक 19 जुलाई 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./08/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400006/8 वर्ष 2016-17
ग्राम वच्चे, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/1427/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम वच्चे, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अभिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
(1)	(2)	(3)	(4)	ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	वच्चे	अंतागढ़	श्यामलाल पिता सुखराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.28	0.69	एक फसली	-	छेना-0.3, छेना-0.35, छेना-0.45, छेना-0.35,	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									छेना-0.35 छेना-0.4, छेना-0.55, छेना-0.5, साजा-1.6, साजा-1.4, महुआ-1.1, जामुन-0.5	
2.	वर्चे	अंतागढ़	मनारोबाई पिता सिंगलूराम, गोंड	आर. एफ./695 में से	0.48	1.19	एक फसली	-	साजा-1.35, साल-1.3, महुआ-0.9, तेंदू-1.6, धोबिन-0.6, भेलवा-1.2, महुआ-0.55, साल-1.5, साजा-1, साल-1.2, महुआ-0.9, साजा-1.15 महुआ-0.9, महुआ-0.9 महुआ-0.65, महुआ-1.2, महुआ-1, महुआ-0.9, साजा-1, महुआ-1.2, महुआ-1.5, महुआ-1,	
3.	वर्चे	अंतागढ़	घसियाराम पिता मेरसिंह, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.10	0.25	एक फसली	-	साजा-1.5, महुआ-0.6, साजा-1.5, महुआ-1.8, साल-0.3, रेहान-0.9, कर्मा-0.5, तेंदू-0.6, तेंदू-1.5, साजा-0.5, साल-0.5, साल-1.2, साजा-0.8, साल-0.9, साल-1, साल-0.9, साल-1.1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	वर्चे	अंतागढ़	सोनसिंह पिता सनकुर, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.38	0.95	एक फसली	-	धावड़ा-2, साजा-2.3, मोदगा-2.35, सागौन-0.4, सिंदुर-1.35, सागौन-0.6, बरगद-1.85, सागौन-1.3, कुम्ही-1.9, तेंदू-1, मोदगा-1.4	
5.	वर्चे	अंतागढ़	भुवनलाल पिता जगताराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.52	1.28	एक फसली	-	महुआ-2.9, साजा-1.1, साजा-1.1, करा-0.7, साल-2.5, महुआ-0.55, कुम्ही-1.2, सागौन-0.6, महुआ-0.55, सागौन-0.85, कुसुम-2.8 साजा-1.6, सागौन-1.7, साजा-2.3, साजा-1.6, तेंदू-1.7, छेना-0.7, तेंदू-1.6	
6.	वर्चे	अंतागढ़	भुनेश्वर पिता वल्लीराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.09	0.22	एक फसली	-	साजा-1, रेहान-0.8, धावड़ा-1, साजा-1.1, तेंदू-0.9, कहवा-0.8, करा-0.3, करा-0.4, धोबिन-0.85, करा-0.3, साजा-0.85, धावड़ा-0.5, साजा-0.9, रेहान-0.6, रेहान-0.45, करा-0.3, रेहान-0.65, करा-0.4, करा-0.4, रेहान-0.6, रेहान-0.35,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									साजा-0.35, धावड़ा-0.4, रेहान-0.4, कर्मा-0.3, साल-0.3, साल-0.75, साल-0.55, साजा-0.4, मोदगा-0.55, रेहान-0.3, महुआ-1.1, साल-1.2, साजा-1.2, रेहान-0.65, रेहान-0.75, कर्मा-0.75, तेंदू-1.1, साल-0.55, साजा-0.6	
7.	वर्चे	अंतागढ़	अंकालूराम पिता जगताराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	कुसुम-0.3, कुसुम-1.4, कुसुम-1, साजा-2, कुसुम-0.75, मोदगा-0.8, सागौन-0.4, मोदगा-0.6, मोदगा-0.6 भेलवा-0.75, भेलवा-0.6, मेदगा-1.2, साल-1.4, हरा-1.3, कुसुम-0.6, खम्हार-1.3, साजा-1.3, कुसुम-0.7, मुंडी-1.46, मोदगा-0.75	
8.	वर्चे	अंतागढ़	रजाऊराम पिता बुधराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.08	0.20	एक फसली	-	साजा-1.6, कुसुम-1, साजा-1, महुआ-1.7, सागौन-1, सागौन-0.6, महुआ-1.3, कर्मा-1.25, साजा-1.6, सागौन-0.75, सागौन-0.8, महुआ-2,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									कुसुम-0.75, कुसुम-0.95, साजा-1.8, कुसुम-1.4, कुसुम-0.7	
9.	वर्चे	अंतागढ़	तुरसिंह पिता सनधर, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	सागौन-0.9, मोयन-1.1, कुसुम-1.6, कुसुम-0.6, कुसुम-2.2, साल-1.3, साल-0.55, कुम्ही-0.75, गिर्ची-0.7, साल-0.8, तेंदू-1.1, कुम्ही-0.9, कुसुम-0.8, साल-0.9, साल-1.1, जामुन-1.3, महुआ-2.4, तेंदू-0.3, मीची-2.1, मिची-1.1, हर्रा-0.7, धावड़ा-0.9	
10.	वर्चे	अंतागढ़	दसऊ पिता डूडी जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.15	0.37	एक फसली	-	महुआ-2.4, महुआ-0.8, कुसुम-1.1, तेंदू-1.2, साल-1.3, रेहान-0.85, तेंदू-0.9, साजा-0.8, साल-2.05, साल-2.3, महुआ-1.4, साल-1.2, साल-1.25, तेंदू-1.3, तेंदू-1, तेंदू-0.4, साल-0.75, साल-1.1, साल-1.1, रेहान-0.6, महुआ-0.45, जाम-0.65,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									तेंदू-0.55, महुआ-0.6, महुआ-1.1, साल-0.8, कर्क-0.4, महुआ-1.4, साल-0.6, रेहान-0.3, रेहान-0.85, रेहान-0.3, साल-1.3, साजा-0.8, कर्क-0.35 धावड़ा-0.65, साल-0.5, साल-0.65 साल-0.4, रेहान-0.6, साल-1.3, रेहान-0.8, तेंदू-0.3, तेंदू-0.5, साल-1.75, साजा-1.1, रेहान-0.9, साल-1, डोडरा-0.65, साल-0.9	
11.	वर्चे	अंतागढ़	रत्नेसिंह पिता कोजा, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	महुआ-1, महुआ-0.7, महुआ-0.7, महुआ-0.6, महुआ-1, बीजा-1.35, साजा-0.65, साजा-0.65, महुआ-0.8, महुआ-1.05, महुआ-2, साजा-1.25	
12.	वर्चे	अंतागढ़	रिंगू पिता सोनुराम, जाति गोंड	आर. एफ./695 में से	0.30	0.74	एक फसली	-	महुआ-1.5, तेंदू-0.4	
कुल योग				12	3.07	7.6				

आज दिनांक 19/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के अधीन पारित किया गया.

अंतागढ़, दिनांक 19 जुलाई 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./33/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201709141400013/31 वर्ष 2016-17
ग्राम कढ़ाईखोदरा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/1428/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि नहकसा जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम कढ़ाईखोदरा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अधिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	कढ़ाईखोदरा अंतागढ़		लच्छनराम पिता मानूराम	पी.आर. एफ. 970, में से	0.48	1.19	एक फसली	निरंक		नहकसा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु
				पी.आर. एफ. 971 में से	0.52	1.28	एक फसली	निरंक		
				योग	2	1.00	2.47			
2.	कढ़ाईखोदरा अंतागढ़		कुंवरसिंह पिता बीरूराम	पी.आर. एफ. 971 में से	2.11	5.21	एक फसली	निरंक		
				योग	1	2.11	5.21			
				महायोग	3	3.11	7.68			

आज दिनांक 19/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से पारित किया गया.

अंतागढ़, दिनांक 19 जुलाई 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./06/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400004/6 वर्ष 2016-17
ग्राम आतुरबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/1429/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि आतुरबेड़ा जलाशय नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम आतुरबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के

लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं। अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अभिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	सुदराम माता सनारोबाई, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.27	0.67	एक फसली	निरंक	महुआ-4.50	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण
2.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	खांडू पिता रूपजी, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.10	0.25	एक फसली	निरंक	महुआ-3.00, महुआ-2.60, महुआ-1.90	
3.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	आयतुराम पिता चैन, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.18	0.44	एक फसली	निरंक	-	
4.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	जानकु पिता उदेल्, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.13	0.32	एक फसली	निरंक	-	
5.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	बजारूराम पिता जगदेव, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.24	0.59	एक फसली	निरंक	-	
6.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	स्व. सेगरूराम पिता पनामी, जाति गोंड के आश्रित परिवार	आर. एफ./764 में से	0.10	0.25	एक फसली	निरंक	-	
7.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	जुगरूराम पिता स्व. दुर्गु, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.10	0.25	एक फसली	निरंक	कुसुम-4.00	
8.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	रस्सु राम पिता बुधराम, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.07	0.17	एक फसली	निरंक	साजा-1.20, तेंदू-1.00, महुआ-3.10, महुआ-2.60, कुसुम-1.20, तेंदू-1.90, महुआ-1.70, महुआ-1.70	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	लखुराम पिता शंकर, जाति-गोंड	आर. एफ./764 में से	0.58	1.43	एक फसली	निरंक	तेंदू-1.60, तेंदू-1.60, तेंदू-2.30, तेंदू-1.60, तेंदू-1.50, सेनहा-0.90, सेनहा-0.70, तेंदू-2.50, महुआ-2.60, नीम-0.50, नीम-0.50, अन्य-0.60, अन्य-0.60	
10.	आतुरबेड़ा	अंतागढ़	गड़वा राम पिता बुधराम, जाति गोंड	आर. एफ./764 में से	0.79	1.95	एक फसली	निरंक	चार-0.60, चार-0.60, कुसुम-0.40, धौड़ा-1.80, बेहड़ा-1.30, अन्य-0.90 साजा-1.00, साजा-1.00, साजा-1.10, धौड़ा-0.90, महुआ-2.60, महुआ-2.50, तेंदु-1.20	
कुल योग					2.56	6.32				

आज दिनांक 19/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के अधीन पारित किया गया.

अंतागढ़, दिनांक 19 जुलाई 2021

उद्घोषणा-पत्र

**भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./07/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400005/7 वर्ष 2016-17
ग्राम पोटेबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़**

क्रमांक/1432/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि आतुरबेड़ा जलाशय नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम पोटेबेड़ा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अभिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक

एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	जयसिंह कोडया, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.46	1.14	एक फसली	-	साजा-2.6	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण
2.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	इतवारू पिता सनऊ, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	निरंक	
3.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	मंगलू पिता मतेर, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.22	0.54	एक फसली	-	निरंक	
4.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	समसाय पिता बिरजू, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.30	0.74	एक फसली	-	चार-0.2, कर्मा-0.7, महुआ-0.7, तेंदू-1, साल-1.1, साल-1.4, साल-1.1, जामुन-1.3, तेंदू-0.6, साल-1.4, जामुन-1.3, साल-1.1, महुआ-0.9, तिलसा-0.8, साल-0.8, साल-1.5, साजा-1, साल-1.5, महुआ-0.8, साल-2, साल-1, महुआ-0.9, तेंदू-1.1, महुआ-0.8, कर्मा-0.8, साजा-1, महुआ-0.4, साल-2.3, जामुन-1.1, साल-1.5,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									साल-1.6, साल-1.4, साल-1.2, तेंदू-0.9, साल-1.3, महुआ-0.7 साजा-1, धौड़ा-0.8, साजा-1.2, साल-1.2, महुआ-1.05	
5.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	सनोतिबाई पिता सनऊ, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.22	0.54	एक फसली	-	साल-1.8, साल-1.7, महुआ-1, तेंदू-1.5, महुआ-1.7, कुसुम-1.2, तेंदू-0.6, साजा-1.2	
6.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	घसिया पिता दुराराम, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.15	0.37	एक फसली	-	छिंद-500	
7.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	सियाराम पिता दयालू जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.23	0.57	एक फसली	-	साजा-2.1, साजा-2, साजा-2.2, महुआ-2.1, महुआ-3, साजा-1.1	
8.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	महंगू पिता सुखराम, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.21	0.52	एक फसली	-	साजा-1.6, सागौन-2, छिंद- सागौन-0.4, तेंदू-1.5, साजा-1.4, तेंदू-1.5, महुआ-2.2, छिंद- सेनहा-0.5, सेनहा-0.7,	
9.	पोटेबेड़ा	अंतागढ़	सुखदेव पिता दुवारू, जाति-गोंड	आर. एफ./696 में से	0.40	0.990	एक फसली	-	निरंक	
योग				9	2.42	5.98				

आज दिनांक 19/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के अधीन पारित किया गया.

अंतागढ़, दिनांक 19 जुलाई 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./09/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201708141400007/9 वर्ष 2016-17
ग्राम मड़पा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/1433/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम मड़पा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं। अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अभिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	मड़पा	अंतागढ़	बिसनु पिता जग्गू जाति गोंड	आर. एफ./694 में से	0.09	0.22	एक फसली	-	कुसुम-1.7, मोदगा-1.4, मोदगा-0.6, मोदगा-1.2, कहुआ-0.5, कहुआ-0.4, कढरी-0.6, महुआ-1.5, कर्रा-0.9, कर्रा-0.9, महुआ-1.8, मोदगा-0.6, महुआ-1.2,	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण
2.	मड़पा	अंतागढ़	शम्भूराम पिता मेरसिंह जाति गोंड	आर. एफ./694 में से	0.12	0.30	एक फसली	-	कर्रा-0.8, धावड़ा-1.1, कर्रा-0.65, कर्रा-0.85, रेहान-1.2, कर्रा-0.8, कर्रा-0.6, तेंदू-1, तेंदू-1.3, तेंदू-0.9, कर्रा-0.5, साजा-1.3, महुआ-1.8, कर्रा-1,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									छेना-0.9, कर्रा-0.7, कर्रा-0.7, कर्रा-0.8, सेन्हा-0.9, कर्रा-0.7, कर्रा-0.7, कर्रा-0.8, साल-1.6, महुआ-1.6, महुआ-0.7, कर्रा-1, सेन्हा-1.55, तेंदु-1.5, साजा-1.5,	
3.	मड़पा	अंतागढ़	करमू पिता मेहरसिंह, जाति गोंड	आर. एफ./694 में से	0.28	0.70	एक फसली	-	साजा-0.6, मुंडी-0.3, मुंडी-0.3, कुसुम-1.9, महुआ-0.5, साजा-0.8, महुआ-1.05, सागौन-0.3	
4.	मड़पा	अंतागढ़	सुरजू पिता चमरू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.07	0.17	एक फसली	-	महुआ-1.2, महुआ-1, कुसुम-1.2, महुआ-0.8, कुसुम-0.85 फरसा-1.1, महुआ-1.85, फरसा-0.3, महुआ-0.75, सागौन-0.6, कुसुम-0.65, कुसुम-0.55 फरसा-0.5, धावड़ा-0.3, कर्रा-1.2, अन्य-0.6, अन्य-0.6, अन्य-0.6	
5.	मड़पा	अंतागढ़	बिरजू पिता चमरू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.16	0.40	एक फसली	-	कुसुम-0.35, साजा-1.6, सागौन-0.35, तेंदू-0.6, महुआ-0.95, सेन्हा-1.65, महुआ-1.1,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									कर्मा-0.65, कर्मा-0.6, कर्मा-0.3, कर्मा-0.5, कर्मा-0.3, कर्मा-0.5, तेंदू-1.4, कुसुम-0.6, महुआ-1, साजा-1.4, महुआ-1.55	
6.	मड़पा	अंतागढ़	रामू पिता करमू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.28	0.70	एक फसली	-	धावड़ा-1.9, सागौन-0.7, साजा-1.6, सागौन-0.4, महुआ-1.7, महुआ-1.25, महुआ-2.15	
7.	मड़पा	अंतागढ़	बिरेन्द्र पिता जग्गू, गोंड	आर. एफ./694 में से	0.09	0.22	एक फसली	-	तेंदू-0.3, कर्मा-0.3, महुआ-0.5, रेहान-0.4, अन्य-0.45, महुआ-0.4, साजा-0.5, साजा-0.6, साजा-0.5, साल-0.3, कर्मा-0.3, महुआ-0.5, साजा-0.85, साल-0.9, रेहान-1, अन्य-0.5, रेहान-0.7, साजा-0.45, रेहान-0.3, रेहान-0.35, रेहान-0.3, रेहान-0.3, महुआ-0.35, महुआ-0.7, महुआ-0.85, महुआ-1.1, रेहान-0.6, साल-0.75, महुआ-0.9, साल-0.7, साल-0.45,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
									महुआ-0.95, साजा-0.8, आम-0.4, रेहान-1, रेहान-0.35, रेहान-0.65, रेहान-0.55, रेहान-0.75, रेहान-0.6, महुआ-0.75, तेंदू-0.9, तेंदू-0.5, महुआ-0.8, तेंदू-0.9, महुआ-3, साल-0.4, तेंदू-1.2, महुआ-1, महुआ-0.4, साजा-1.4, साजा-1.1, तेंदू-1.4, साल-1.5, साजा-1.3, महुआ-1		
कुल योग				7	1.09	2.71					

आज दिनांक 19/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के अधीन पारित किया गया.

सही/-
अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
एवं भू-अर्जन अधिकारी.

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2021

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक 701/छ.ग.रा.मं./बिलासपुर/2021.—Certified that we have in the FN of this day on 31-07-2021 respectively relieved charge of the office of the President Board of Revenue, C.G., Bilaspur.

Relieved Officer : C. K. Khaitan

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2021

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक 702/छ.ग.रा.मं./बिलासपुर/2021.—Certified that we have in the FN of this day on 04-08-2021 respectively received charge of the Office of the Member, Board of Revenue, C.G., Bilaspur vide GAD's order No. E-1-01/2021/एक-2, Nawa Raipur, dated 31-07-2021 and that the officer receiving charge travelled during joining time on + P.M. (mention dates).

Relieving Officer : UMESH KUMAR AGARWAL

हस्ता./-
अवर सचिव.

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2021

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/1(6)/48/सं.का./2019.—Certified that we have in the afternoon of this day respectively made over and received charge of the office of Secretary, Parliamentary Affairs Department in pursuance of GAD order No. E-1-08/2021/1-2, Dated 02-08-2021 and that the officer receiving charge traveling during joining time on 02-08-2021 (mention date)

Relieved Officer : Sonmoni Borah I.A.S.

Relieving Officer : Avinash Champawat I.A.S.

हस्ता./-
अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st July 2021

No. 491/Confdl./2021/II-2-1/2021.—Shri Vinod Kumar Dewangan, I Additional District and Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) and senior-most Judicial Officer posted at District Headquarter, Dakshin Bastar (Dantewara) is, hereby, appointed as Officiating District and Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) with effect from the date of taking over charge of his duties until the posting of regular District and Sessions Judge, with a direction to discharge the duties of District and Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara), in addition to his own duties, until further orders.

Bilaspur, the 1st July 2021

No. 6187/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under Clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Smt. Soni Tiwari, J.M.F.C., Mahasamund to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Bilaspur, the 2nd July 2021

No. 500/Confdl./2021/II-3-1/2021.—In partial modification of Registry Order Nos. 485-486/Confdl./2021/II-3-1/2021 dated 01-07-2021 and 488/Confdl./2021/II-3-1/2021 dated 01-07-2021, the Judicial Officers of the Lower Judicial Service of the State, who have been transferred/posted vide these orders, are, hereby directed, to hand over charge of their present post after the National Lok Adalat scheduled to be held on 10-07-2021 and join at their new place of posting on or before 24-07-2021.

Bilaspur, the 2nd July 2021

CORRIGENDUM

No. 502/Confdl./2021/II-3-1/2021.—In Registry Order No. 488/Confdl./2021/II-3-1/2021 dated 01-07-2021 :

1. In Sl. No. 3, Column No. 6 be read as 'II Civil Judge Class-II' instead of III Civil Judge Class-II and.
2. In Sl. No. 35, Column No. 6 be read as 'Civil Judge Class-II' instead of I Civil Judge Class-II.

Bilaspur, the 14th July 2021

No. 6786/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Shri Mayank Soni, J.M.F.C. Surajpur, Presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Mungeli to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2021

क्रमांक 6788/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुंगेली अपने घोषित कार्य स्थल मुंगेली के अतिरिक्त लोरमी में भी प्रत्येक माह में दो सप्ताह (द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह) श्रीमती बरखा रानी वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, लोरमी के मातृत्व अवकाश से वापसी तक बैठक करेंगे.

No. 6788/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers Conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Mungeli in addition to his place of sitting at Mungeli declared shall also sit at Lormi for 2 weeks (2nd & 3rd week) in every month till return of Smt. Barkha Rani Verma, Civil Judge Class-II, Lormi from Maternity leave.

Bilaspur, the 16th July 2021

No. 6892/Rules/2021.—The "Rules for Video Conferencing for Courts of the Chhattisgarh State", which were notified by the High Court of Chhattisgarh vide notification No. 5785/Rules/2020 dated 27-06-2020, shall be deemed to have come into force with effect from 27-06-2020 i.e. the date when the rules were notified by the High Court.

Bilaspur, the 16th July 2021

No. 6894/Rules/2021.—The “e-filing Rules, 2020”, which were notified by the High Court of Chhattisgarh vide notification No. 6102/Rules/2020 dated 10-07-2020, shall be deemed to have come into force with effect from 10-07-2020 i.e. the date when the rules were notified by the High Court.

Bilaspur, the 22nd July 2021

No. 615/Confdl./2021/II-3-1/2021.—Registry Order No. 488/Confdl./2021/II-3-1/2021 dt. 01-07-2021 is modified to the extent that at Sl. No. 60, the transfer/posting of Shri Rahul Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Durg as IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg, Stands cancelled and at Sl. No. 23, Ku. Namrata Norge, V Civil Judge Class-II, Raipur stands transferred and posted as IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg instead of I Civil Judge Class-II, Kota, District-Bilaspur.

Bilaspur, the 22nd July 2021

No. 616/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below, is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Kerketta, XIII Civil Judge Class-II.	Durg	Kota	Bilaspur	I Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 23rd July 2021

No. 620/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below, is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Savita Singh Thakur, II Civil Judge Class-II.	Balod	Durg	Durg	X Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 29th July 2021

No. 7320/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Anjali Singh, J.M.F.C., Korba	Korba	Korba
2.	Ku. Dolly Dhruw, J.M.F.C., Katghora	Katghora	Korba

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2021

क्रमांक 184/दो-3-43/2007.—श्री राजेन्द्र प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा दिनांक 30-06-2021 की अपराह्न में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक, में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 31st July 2021

No. 7414/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Smt. Shradha Singh, J.M.F.C. Bastar at Jagdalpur to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2021

क्रमांक 191/दो-3-16/2021.—श्रीमती नीरू सिंह, तत्कालीन द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग वर्तमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-06-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.